KUMARI SELJA: Sir, as in the rest of the country, even in the North-East, we have a lot of disparities. In Mizoram, the literacy rate is as high as 82.3 per cent, according to the 1991 Census, whereas in Arunachal Pradesh the literacy rate is about 41 per cent. So, while, I think, we need to replicate this kind of thing even in the North-East itself, we would certainly like to learn from the example set by Mizoram and replicate it elsewhere, including the North-East and the rest of the country.

SHRI K. R. JAYADEVAPPA: Sir, the Government of India is spending huge amounts of money to decrease the illiteracy, but unfortunately, the money being allotted for this is not being properly utilised. What steps has the Government taken so far to check this misuse, and how many cases of misuse have so far been brought to the notice of the Government? I would like to know this from the hon. Minister.

KUMARI SELJA: Sir, we try to see that the money is managed very well because, after all, considering the resource crunch and the amount of money that has been given to education, we need to see that we spend the money very well and that constant monitoring takes place. Despite that, if there is any specific case which the hon. Member has in mind, we would be very happy to look into it so that the money is not frittered away.

प्राथमिक स्कूलों के संबंध में एन०सी० ई०आर०टी० का प्रतिवेदन

*165. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) ने 1989 में देश के 23 राज्यों के 60,000 प्राथमिक स्कूलों के संबंध में अध्ययन प्रारंभ किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त अध्ययन का प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है जिसमें प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर चिन्ता व्यक्त की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने देश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) ने वर्ष 1989 में देश के 23 राज्यों के 4838 प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की उपलब्धि पर एक अध्ययन आयोजित किया । यह प्रतिवेदन दिसम्बर, 1994 में प्रकाशित हुआ । इस प्रतिवेदन में यह दर्शाया गया है कि इस अध्ययन में शामिल किए गए प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन के स्तर सामान्यत: निम्न है ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के शुरू होने से, भारत सरकार, ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड और शिक्षक शिक्षा जैसी योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों को सहायता दी है । गुणवत्ता ने सुधार करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां भी तैयार की गई हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदया ने यह स्वीकार किया है कि एन०सी०ई०आर०टी० के एक ग्रुप ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा के बारे में एक अध्ययन किया था, जिसकी रिपोर्ट दिसम्बर, 1994 में प्रकाशित हुई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि हमारे यहां प्राथमिक स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। अपने प्रश्न के अगले भाग में मैंने यह जानना चाहा था कि इस गिरते हुए स्तर को उठाने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है तो इसके जवाब में मंत्री महोदया ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1986 में आपरेशन ब्लैकबोर्ड और टीचर एजुकेशन जैसी योजनायें चलाकर हमने शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयत्न किया है। सभापति जी, 1994 में जताई गई चिंता का समाधान 1986 की योजनाओं का हवाला देकर दिया जाये, इससे बड़ी हास्यास्पद बात दूसरी हो नहीं सकती। क्योंकि जिन योजनाओं के चलते हुए आठ साल हो गए थे, उनका असर—अच्छा या बुरा, इसका अध्ययन एन०सी०ई०आर०टी० का ग्रुप कर चुका है। उसके बाद 1994 की रिपोर्ट में एन०सी०ई०आर०टी० का स्टडी ग्रुप कह रहा है कि हमारे यहां प्राथमिक स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। तो मैं मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि दिसम्बर, 1994 की इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या सरकार ने इस चिंता का समाधान करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है, क्या इसके बारे में कोई बैठक हुई है? जो चिंता स्टडी ग्रुप ने दर्शायी है, क्या उसका नोटिस सरकार ने लिया है? इसका समाधान करने के लिए सरकार ने क्या किया है यह मैं जानना चाहती हूं?

कुमारी शैलजा: जो माननीय सदस्या ने स्टडी ग्रुप के बारे में बात कही है यह हमारी शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा हैं मिड सिक्सटीज में एक स्टडी हुई थी और उसके बाद भी हुई। उसका कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं था। इसका यह मतलब है कि जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको कान्सटेंटली हम अप-ग्रेड कैसे करते रहें, उनकी क्वालिटी हम कैसे ऊपर लायें। उसका यह एक मकसद था। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो प्राइमरी एजुकेशन की स्पेसिफिक बात कही है, हमने इसके लिए एक जनरल स्टडी की। मोड आफ एकेडेमिक नेचर, इसकी हमने स्टडी की और इसका स्टैंडर्ड हम किस तरह ऊपर ला सकें, प्राइमरी एजुकेशन का हमने इसकी एक बेस लाइन स्टडी की, जो कि ज्यादा स्पेसिफिक थी। इस पर बेस करके हमने प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन इसमें जो कन्सर्न दर्शाया गया है उसको हम कांसटेंटली इनकारपोरेट करते रहे हैं और एजुकेशन का, शिक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके लिए स्कीम चल रही है और उनको समय-समय पर जैसे-जैसे आवश्यकता होगी हम इसको इनकारपोरेट करते जायेंगे। जो स्टडी में कन्सर्न दर्शाया गया है उनको हम जैसे जैसे आवश्यकता होगी इनकारपोरेट करते जायेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मंत्री महोदया ने बेस लाइन स्टडी की बात की है, स्पेसिफिक स्टडी की बात की और कान्सटेंट मोनेटरिंग की बात की है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं और वे स्वयं शायद इस बात को स्वीकार करेंगी कि इन सारी स्टडीज के बावजूद, आपकी कान्सटेंट मानेटरिंग के बावजूद वस्तुस्थिति यह है कि आज भी देश में जो तमाम बच्चे स्कूलों में होने चाहिएं वे—पहली बात कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी बच्चे नहीं हैं और जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वे वहां टिकते नहीं हैं। ड्राप आउट प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज्यादा है। और जो वहां टिक भी रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अध्यापक हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं और जो अध्यापक उपलब्ध भी हैं उनकी योग्यता पर बहुत बड़ा प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ है। इन सारी चीजों को मिलाकर प्राइमरी शिक्षा का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक चित्र हमारे देश में दिखायी दे रहा है। मुझे खुशी है कि

कापन हेगन सम्मेलन में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता जताई और पैसा लेने की बात भी की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि इतना बड़ा चिंताजनक चित्र देश में प्राइमरी शिक्षा का बना है जो कि उच्च शिक्षा की नींव होता है। इसके बारे में केवल कान्सटेंट मानेटरिंग से क्या होगा ? इसके लिए तुरंत कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो मैं मंत्री महोदया से इस बारे में अपनी चिंता को शेयर करते हुए पूछना चाहूंगी कि क्या वे इस बारे में कोई ठोस कदम उठाने की तरफ ध्यान देंगी या उन्होंने इस बारे में कोई उपाय किए हैं ? अगर किए हैं तो क्या वे उनसे सदन को अवगत करायेंगी ?

कुमारी शैलजा : महोदय, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, हमने इसी चीज को देखते हुए और जो कंसर्न अभी माननीया सदस्या ने भी प्राइमरी एजुकेशन का दर्शाया है, यह बेसलाइन स्टडी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही की है ताकि उसको हम अपग्रेड कर सकें तथा क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकें। इसके लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम आरम्भ किया है, वह डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है जो हमने इसी वर्ष में 43 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 स्टेट्स में लागू किया है। इसको हम और भी आगे बढ़ायेंगे और आठवीं प्लान में 110 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। अगर बहुत अच्छा रिस्पोंस मिलता है तो और भी जल्दी पूरे देश में इसको आगे बढ़ायेंगे।

MR. CHAIRMAN: Mr. Ram Jethmalani, not here. Shrimati Sarala Maheshwari

श्रीमती सरला माहेश्वरी : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मेरी गुजारिश को स्वीकारा। सभापति महोदय, बहरहाल मैं इस प्रश्न के संबंध में माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है साक्षरता के संबंध में और शिक्षा के स्तर में जिस तरह से गिरावट आती जा रही है, क्या यह सत्य है, क्या आप इस बात से अभिज्ञ हैं कि हाल ही में जिन देशों में आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक के निर्देशों पर जो ढांचागत समायोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के तहत उन देशों के शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आई है खास कर के अमीरों और गरीबों के बीच में अंतराल बढ़ता जा रहा है और गरीब बच्चों के शिक्षा के स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है। यह बात मैंने नहीं कही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों के अधिकारों को ले कर जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अध्यक्ष हमबर्गर ने यह बात कही है। क्या हमबर्गर की इस रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान गया है और अगर गया है तो आपने इन तथ्यों को देखते हुए कोई हमारे देश में सर्वे करवाया है ? हमारे देश में इसके क्या परिणाम निकल रहे हैं ? हमारे देश में जहां शिक्षा की हालत पहले से ही बहुत कमजोर है और अब जब शिक्षा के निजीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, हमारे बच्चों के प्राथमिक शिक्षा स्तर पर क्या असर पड़ रहा है ? इसके अलावा इसके साथ एक अहम सवाल है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और हमारे देश के बहुत से बुद्धिजीवियों ने भी बार-बार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि हमारी जो शिक्षा की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का स्तर भी बहुत ठीक नहीं है, अनेकानेक साम्प्रदायिक तत्व उनमें मौजूद हैं। उन किताबों के स्तर को सुधारने के लिए आप क्या करने जा रही हैं ?

कुमारी शैलजा : सभापति महोदय, यह दो प्रश्न हैं। पहले का जवाब मैं यह देना चाहूंगी कि जो एक्सटर्नल फंडिंग की बात है, उसमें हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि जो बाहर से हमें एजेंसीज फंड दे रही हैं, वह हमारे ऊपर किसी प्रकार की कंडीशंस न लगायें। इसके लिए गाइडलाइंस भी हैं जिनको हमने माना है। जब यूरोपियन कम्युनिटी से, आई.डी.ए. से यह डिसकशन की जा रही थी तो यह बात रखी गई थी कि उनकी कोई कंडीशनेलिटीज हमारे ऊपर लागू नहीं होंगी, उनकी

मॉनिटेरिंग होगी। जो भी कार्यक्रम के तहत हम करेंगे वह हम अपने हिसाब से करेंगे, जो हमारी कंडीशंस को सूट करता है, वह हम करेंगे। तभी हमने यह एक्सटर्नल फंडिंग लागू की थी। आपने जो दूसरी बात कही है वह थोड़ी मूल प्रश्न से भिन्न है लेकिन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपने साम्प्रदायिक एलीमेंटेस की बात की है। उसके लिए हमने एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है जो करिकुलम को देखती है। इस तरह का एलीमेंट अगर कहीं आ जाता है किसी ऐक्ट बुक में तो उसकी हम स्टडी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए बोलते हैं। जो बोर्ड करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनल इंट्रेस्ट को देखते हुए, नेशनल इंटेग्रेशन को देखते हुए और दूसरी वेल्यूज को देखते हुए उनको ही फालो किया जाए, उसमें यह बात रखी गई है।

श्री विष्णु कांत शास्त्री : माननीय सभापति जी, संविधान में अपने देश को इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सचमुच दो देश हो गये हैं एक इंडिया और एक भारत। बड़े बड़े नगरों में, जो इंडिया है, प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से चलती है। अपने देश के जो अच्छे विद्या संस्थान हैं, उनमें प्राइमरी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से चलती है। इसकी नकल पर अब कस्बों में, गांवों में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। मैं माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दी जाए, इस सर्वजन स्वीकृत सिद्धांत को जिस सिद्धांत को सारी दुनिया मानती है, उसे हमारे देश में भी बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा? क्या इसके लिए कोई प्रभावी कदम आप उठायेंगी? व्यवसाय के रूप में, स्टेटस सिम्बल के रूप में जो अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। उन पर रोक लगाने का कोई प्रभावी कदम क्या वे उठायेंगी, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं?

कुमारी शैलजा : इसमें जहां तक इन स्कूलों पर रोक लगाने की बात है तो इसमें यहां से सैन्ट्रल गवर्नमेंट लेवल पर तो क्या कह सकते हैं, यह तो लोकल गवर्नमेंट को ही देखना पड़ता है अपने रुल्ज एंड रेगुलेशंस, अपने लाज के तहत कि वे उनको बन्द करना चाहेंगे या उनको चलने देना चाहेंगे और जहां तक मातृभाषा की बात है तो यह तो पहले से ही हमने कहा है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन दी मदर टंग।

श्री विष्णु कांत शास्त्री : जो नये विद्यालय खुल रहे हैं बड़े नगरों में क्या उनका शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है या फिर उनका अधिकाधिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता जा रहा है? इस पर कुछ प्रकाश डालिए और इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या करना चाहती है?

कुमारी शैलजा : यह कन्करेंट लिस्ट पर है यह तो माननीय सदस्य को मालूम ही है और यह तो The respective State Governments can take a decision in this regard

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, we have observed over the Five-Year Plan period that there has been a sectoral imbalance so far as the allocation to the primary education sector is concerned. There has been a gradual diminution in regard to the primary education sector vis-a-vis the other sectors of education. Now, at the present point of time, we are hearing so much about the economic reforms and all that. In that context, we are also hearing about the 'East-Asian Miracle'. One of the studies points out that a major factor *which contributed to the* phenomenal economic growth of the East-Asian countries was the kind of investment they had for their primary education sector. In China, Taiwan, South Korea and all those countries, this is the general lesson. So, I would like to know whether the Government contemplates to reverse the relative sectoral imbalance, the gradual

diminution of outlay for primary education, that has been there compared to the other sectors of education.

कुमारी शैलजा : सर ऐसी बात नहीं है, यह एलीमेंटरी एजुकेशन के लिए तो आउटले बढ़ता ही जा रहा है।

In fact, in the Seventh Plan, the outlay for elementary education was 37 per cent of the total outlay for education. And it has increased in the Eighth Plan to 46 per cent. So, it has increased and not decreased.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: In reply to parts (a) to (c) of the question, it is stated by the Minister, "The report brings out that learning levels are generally low in primary schools covered by the study". I would like to know from the Minister the main reason for the low levels in primary schools. Is it because of poverty or is it because of child employment and all that? And what is the remedy that has been suggested by the Committee?

KUMARI SELJA: Sir, there are many reasons for this low level of learning. To counter this, we have prescribed the MLL, the Minimum Levels of Learning that should take place. To improve this, I think, we need to improve the Teacher Training also for which purpose we are setting up the District Institutes of Education and Training. I think that will go a long way in improving the position. Along with this, under the Operation Blackboard, we are giving teaching-learning material and we are providing extra rooms and extra teachers. I think that will also help to a great extent. Of course, there is also the scheme of the District-Primary Education Programme.

MR. CHAIRMAN: Question No. 166.

Survey by DDA regarding lease condition

*166. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the D.D.A. is surveying the old lease entered by the former Delhi Improvement Trust to identify how the lease conditions had been violated.

(b) whether the survey has been completed; and

(c) if so, what is the decision of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Identification of violations of lease conditions is an on-going process. However, such violations are specifically dealt with at the time of renewal or conversion of leases or when otherwise noticed.

(c) No Government decisions are required to deal with the violations of the lease conditions in individual cases.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, one of the functions of the Delhi Development Authority is to find the cases of violation of the lease conditions by the Delhi Improvement Trust, make a survey and thereafter, on the basis of such a survey, take action against persons who have violated the said conditions. Sir, the Minister's reply is very general. I do not blame the Minister because now the DDA itself has become a white elephant. The DDA instead of evenly developing Delhi, is itself involved in favouritism and nepotism. The DDA is giving flats to the people who are ineligible. Therefore, I do not expect the hon. Minister to take action because the DDA will take action in respect of such a violation. (*Interruptions*) Yesterday, there was a news-item stating that for the purpose of removing encroachments, the DDA has done nothing in spite of the complaints. The hon. Minister has said in his reply that no survey has been done. The Minister says: "As soon as we get a complaint, we take action. Otherwise, such violations are specifically dealt with at the time of renewal or conversion of leases." It is the primary duty of the DDA to find out the cases of violation of the lease conditions. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please ask the question now. Please come to the question now. If you want any reply, you ask the question quickly.